

नरियात तत्परता सूचकांक 2021: नीतिआयोग

प्रलमिस के लयि:

नरियात तत्परता सूचकांक, नीतिआयोग, सकल घरेलू उत्पाद के घटक ।

मेन्स के लयि:

सरकारी नीतयिँ और हस्तक्षेप, संसाधन जुटाना, आर्थिक वकिस दर में तेजी से वृद्धि हासलि करने के लयि नरियात, नरियात प्रोत्साहन के मुद्दों हेतु चुनौतयिँ और आगे की राह ।

चर्चा में क्योँ?

नीतिआयोग द्वारा जारी नरियात तत्परता सूचकांक (Export Preparedness Index- EPI), 2021 के अनुसार, गुजरात को लगातार दूसरे वर्ष नरियात तैयारयिँ के मामले में भारत का शीर्ष राज्य नामति कया गया है ।

- सूचकांक में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमलिनाडु क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं, क्योँकि उच्च औद्योगिक गतविधियिँ के साथ समुद्र तटीय बंदरगाहों वाले राज्य भारत के अधिकांश नरियात के लयि ज़मिमेदार हैं ।

नरियात तत्परता सूचकांक (EPI):

- चुनौतयिँ और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतयिँ की प्रभावशीलता को बढ़ाना तथा नरियात के लयि एक सुवधिजनक नियामक ढाँचे को प्रोत्साहति करना ।
- सूचकांक में 4 स्तंभ, 11 उप स्तंभ और 60 संकेतक शामिल हैं तथा इसमें 28 राज्य एवं 8 केंद्रशासति प्रदेश शामिल हैं ।
- चार स्तंभ:
 - नीति: नरियात और आयात के लयि रणनीतिक दशिया प्रदान करने वाली एक व्यापक व्यापार नीति ।
 - बज़िनेस इकोसिस्टम: एक कुशल बज़िनेस इकोसिस्टम जो राज्योँ को नविश आकर्षति करने और स्टार्ट-अप शुरू करने हेतु व्यक्तयिँ के लयि एक सक्षम बुनयिादी ढाँचा बनाने में मदद करता है ।
 - नरियात पारसिथितिकी तंत्र: कारोबारी माहौल का आकलन करना, जो नरियात के लयि वशिषिट हो ।
 - नरियात प्रदर्शन: यह एकमात्र आउटपुट-आधारति पैरामीटर है जो राज्योँ और केंद्रशासति प्रदेशोँ के नरियात गतविधियिँ की जाँच करता है ।
- ग्यारह उप-स्तंभ:
 - सूचकांक में 11 उप-स्तंभोँ- नरियात प्रोत्साहन नीति; संस्थागत ढाँचा, व्यापारिक वातावरण, आधारभूत संरचना, परविहन कनेक्टविटी, वतित तक पहुँच, नरियात बुनयिादी ढाँचा, व्यापार समर्थन अनुसंधान एवं वकिस अवसंरचना नरियात वविधीकरण और वकिस अभविनियस के आधार पर श्रेणी तैयार की गई है ।
 - सूचकांक की वशिषिताएँ: ईपीआई उप-राष्ट्रीय स्तर (राज्योँ और केंद्रशासति प्रदेशोँ) पर नरियात को बढ़ावा देने के लयि महत्त्वपूर्ण मुख्य क्षेत्रों की पहचान करने हेतु डेटा-संचालन का प्रयास है ।
 - यह प्रत्येक राज्य और केंद्रशासति प्रदेशोँ द्वारा कयि गए वभिन्नि योगदानों की जाँच कर भारत की नरियात क्षमता पर प्रकाश डालता है ।
 - भारतीय राज्योँ/संघ राज्य क्षेत्रों का प्रदर्शन:

Himalayan		
State	Score	Rank
Uttarakhand	40.79	1
Himachal Pradesh	40.43	2
Tripura	27.46	3
Sikkim	27.41	4
Manipur	15.78	5

Coastal		
State	Score	Rank
Gujarat	78.86	1
Maharashtra	77.14	2
Karnataka	61.72	3
Tamil Nadu	56.84	4
Andhra Pradesh	50.39	5

Landlocked		
State	Score	Rank
Haryana	53.20	1
Uttar Pradesh	51.09	2
Madhya Pradesh	51.03	3
Punjab	50.99	4
Telangana	47.92	5

UT/City States		
State	Score	Rank
Delhi	43.66	1
Goa	41.95	2
Jammu and Kashmir	30.06	3
Chandigarh	28.41	4
Puducherry	22.19	5

नरियात तत्परता सूचकांक (EPI) का महत्त्व:

- **राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नरियात प्रदर्शन की जाँच:** इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नरियात प्रदर्शन एवं नरियात हेतु तैयारी की जाँच करना है।
 - सूचकांक के पीछे नहिती वचिर इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को रैंकिंग प्रदान करने हेतु एक बेंचमार्क नरिमति करना है ताकि उनहें इस कषेत्र में एक अनुकूल नरियात वातावरण को बढावा देने में मदद मलि सके।
- **नरियात में आने वाली बाधाओं की पहचान करने में सहायक:** सूचकांक नीति नरिमाताओं और नरियातकों को गति प्रदान करने, बाधाओं की पहचान करने तथा राज्य हेतु एक व्यवहार्य नरियात की रणनीति बनाने और इसकी जाँच करने हेतु एक आवश्यक उपकरण है।
- **राज्य सरकार के लिये पथ-प्रदर्शक:** सूचकांक राज्य सरकारों के लिये नरियात प्रोत्साहन के संबंध में कषेत्रीय प्रदर्शन को चहिनति करने हेतु एक सहायक मार्गदर्शिका होगी और इस प्रकार नरियात में सुधार एवं वृद्धि करने के बारे में महत्त्वपूर्ण नीतितगत अंतरदृष्टि प्रदान करेगा।
- **राज्यों के मध्य प्रतसिपर्द्धा को बढावा:** इसका प्रथमकि लक्ष्य सभी भारतीय राज्यों ('तटीय', 'लैंडलॉकड', 'हमिलयी' और 'यूटी/सिटी-स्टेट्स') के बीच अनुकूल नरियात-संवर्द्धन नीतियों को लागू कर प्रतसिपर्द्धा को बढाना, नयिमों को आसान बनाना, उप-राष्ट्रीय नरियात को बढावा देने व नरियात के लिये आवश्यक बुनयादी ढाँचे का नरिमाण तथा नरियात प्रतसिपर्द्धात्मकता में सुधार हेतु रणनीतिक सफिरशिं प्रदान करना है।

भारतीय नरियात के लिये चुनौतियाँ:

- EPI भारत के नरियात प्रोत्साहन प्रयासों के लिये तीन प्रमुख चुनौतियों की पहचान करता है।
 - नरियात बुनयादी ढाँचे में भनिनता और अंतर-कषेत्रीय वभिदिता।
 - राज्यों में कमज़ोर व्यापार समर्थन और वकिस अभविन्यास।
 - महत्त्वपूर्ण नरियात को बढावा देने हेतु अनुसंधान एवं वकिस बुनयादी ढाँचे की कमी।

भारतीय नरियात के संदर्भ में EPI:

- **नरियात उनमुख भारतीय अर्थव्यवस्था:**
 - जीडीपी = नजिी खपत + सकल नविश + सरकारी नविश + सरकारी खर्च + नरियात-आयात।
 - इस प्रकार नरियात जीडीपी मूल्यों को बढाने के लिये एक आवश्यक घटक है।
 - नरियात भारत के आर्थिक वकिस का एक अवभाज्य घटक है क्योंकि पिछले एक दशक से नरियात भारत के सकल घरेलू उत्पाद में औसतन लगभग 20% का योगदान कर रहा है।
- **कोवडि-19 से रकिवरी:** कोवडि-19 महामारी ने मौजूदा आर्थिक ढाँचे को उलट दिया और वैश्विक व्यापार एवं अर्थव्यवस्था की सुभेद्यता को उजागर किया।
 - कोवडि-19 महामारी के दो वर्ष बाद भी अर्थव्यवस्थाओं पर इसके प्रतिकूल प्रभाव से उबरना बहुत चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
 - हालाँकि भारत ने नरियात में काफी लचीलापन दर्शाया है और रकिॉर्ड स्तर पर उच्च वकिस दर हासलि की है। भारत वतित वर्ष 2021-22 की शुरुआत से नरियात में सकारात्मक आँकड़े दर्ज कर रहा है और दसिंबर 2021 में भारत ने 37 बलियिन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे अधिक नरियात किया है, जो दसिंबर 2020 की तुलना में 37% अधिक है।



increasing 197.03%.

■ **नरियात बढ़ाने का सुझाव:**

- **नरियात अवसंरचना और बाज़ार संकेंद्रण:** बेहतर नरियात प्रदर्शन हेतु विश्वसनीय एवं कुशल नरियात बुनियादी ढाँचे के विकास में निवेश करना आवश्यक है, जो लागत में कमी और नरियात दक्षता में सुधार करने में मदद करेगा।
- **नरियात विविधीकरण की आवश्यकता:** यह नरियात क्षेत्र में स्थिरता एवं विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- नरियात बुनियादी ढाँचे के विकास, उद्योग-अकादमिक संबंधों को मज़बूत करने और नरियात में चुनौतियों का समाधान करने हेतु आर्थिक कूटनीतिके लिये राज्य-स्तरीय जुड़ाव जैसी प्रमुख रणनीतियों पर ज़ोर दिया जाना चाहिये।
- नरियात को बढ़ावा देने में नज़ी क्षेत्र भी अहम भूमिका निभा सकता है।

वर्षों के प्रश्न

प्रश्न: फरवरी 2006 में लागू हुए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2010)

1. अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास।
2. विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना।
3. केवल सेवाओं के नरियात को बढ़ावा देना।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से इस अधिनियम का/के उद्देश्य है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

स्रोत: पी.आई.बी.